

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 मई 2023—वैशाख 15, शक 1945

### विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 21 मार्च 2023

क्रमांक एफ 5-3/2018/1 (एक).—राज्य शासन एतद्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रजनी दुबे, न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर को दिनांक 07 दिसम्बर, 2022 से 09 दिसम्बर 2022 तक (03 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश एवं अवकाश पश्चात् दिनांक 10 दिसम्बर, 2022 तथा 11 दिसम्बर, 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ लेने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय अग्रवाल, संयुक्त सचिव.

**कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग**  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 3 मार्च 2023

क्रमांक/943/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 69 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मण्डी क्षेत्र में प्रदेश के बाहर से लायी गई अधिसूचित कृषि उपज (धान को छोड़कर) पर, प्रति 100 रुपये के मूल्य पर, रु. 0.50 (पचास पैसे) की दर से मण्डी शुल्क तथा रु. 0.25 (पच्चीस पैसे) की दर से कृषक कल्याण शुल्क निर्धारित करती है।

यह अधिसूचना, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च, 2023 तक प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.**

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 3 मार्च 2023

क्रमांक/943/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/943/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2 रायपुर दिनांक 03-03-2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.**

Nava Raipur, Atal nagar the 3rd March 2023

No./943/D-15/116/Part-2/2004/14-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 69 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby, fixes the market Fees at the rate of Rs. 0.50 (fifty paise) and Farmer Welfare Fees at the rate of Rs. 0.25 (twenty five paise) on the value of per 100 rupees on notified agriculture produce (exclude paddy) brought from outside the State into the market area.

This notification shall be effective from 1st April 2022 to 31st March, 2023.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
**K. C. PAIKARA, Joint Secretary**

**गृह (पुलिस) विभाग**  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 11 अप्रैल 2023

क्रमांक एफ-4-02/2014/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्वारा श्री विजय कुमार अग्रवाल (भापुसे-2013), पुलिस अधीक्षक, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ के दिनांक 10-04-2023 से दिनांक 04-05-2023 तक IPS Mid Career Training Phase-III की प्रशिक्षण अवधि में श्री राजेश कुमार अग्रवाल, (भापुसे-2012), सेनानी, 11वीं वाहिनी, छसबल, जांजगीर-चांपा, छ.ग. को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ पुलिस अधीक्षक, जिला जांजगीर-चांपा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**मनोज कुमार श्रीवास्तव**, अवर सचिव.

**खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग**  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 15 मार्च 2023

क्रमांक एफ 5-12/2022/29-2.—राज्य शासन एतद्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 (2019 की सं. 35) धारा 28 की उपधारा 2(क) एवं उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिये अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम 2020 के नियम 6(क) के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा पर निम्नांकित चयनित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अध्यक्ष के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 04 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु इसमें से जो भी पहले हो तक के लिये नियुक्त करता है :—

क्र. (1)	नाम (2)	पता (3)	जिला उपभोक्ता आयोग (4)
1.	श्री गोपाल रंजन पाणिग्रही,	मकान नं. 4, निलांचल विहार कचना रेल्वे क्रासिंग के पास, पो.आ. शंकरनगर, रायपुर.	धमतरी
2.	श्री डाकेश्वर प्रसाद शर्मा,	“बृज छाया”, छत्रपति वीर शिवाजी स्कूल के पीछे, मलसाल तालाब रोड पीयूष नगर, कुशालपुर, रायपुर.	रायपुर
3.	सुश्री रंजना दत्ता,	एल.आई.जी.-72, फेस-2, आर.पी. नगर निहारिका, जिला-कोरबा छ.ग.	कोरबा
4.	श्री आनन्द कुमार सिंघल,	97, जे.पी. विहार, मंगला रोड, बिलासपुर छ.ग.	बिलासपुर
5.	श्री संतोष कुमार	चाणक्य नगर, थाना-सरायढेला डाकघर- के. जी. आश्रम, जिला धनबाद झारखण्ड- 826008.	दुर्ग
6.	श्री राकेश पाण्डेय,	4-बंगलोज, काली मंदिर के पास केदारपुर रिंगरोड अंबिकापुर, जिला सरगुजा छ.ग.	सरगुजा

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	श्रीमती सुजाता जसवाल,	सनसिटी, सन हेरिटेज अपार्टमेंट ए-203, जगदलपुर, जिला-बस्तर छ.ग.	जगदलपुर-बस्तर
8.	प्रशान्त कुन्दू,	सिविल लाईन्स, बंगाली पारा, होटल गुडलक के सामने, तह. व जिला-रायगढ़ (छ.ग.).	जांजगीर-चांपा

## 2. नियुक्ति की शर्तें—

1. जिला आयोग के अध्यक्ष को पदभार ग्रहण करने से पूर्व उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम 2020 के नियम 6(12) के अनुसार शारीरिक स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र तथा नियम 6 (13) के अनुसार शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके कोई वित्तीय अथवा अन्य लाभ नहीं है अथवा नहीं होंगे जिनसे अध्यक्ष के रूप में उसके कार्यकरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो.
2. जिला आयोग के अध्यक्ष के वेतन, भत्ते तथा सेवा की शर्तें छत्तीसगढ़ उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम 2020 के अनुसार होगी.
3. यह नियुक्ति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 तथा उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम 2020 एवं छत्तीसगढ़ उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम 2020 के अध्याधीन होगी.
4. चयनित अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर पदस्थापना जिले में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा. निर्धारित समय सीमा में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

## वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 11 अप्रैल 2023

क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6.—राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम-2002 (यथा संशोधित 2022) में निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात् :—

छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 के (यथा संशोधित 2022) के नियम-3 के अधीन परिशिष्ट-1 सूची में निम्नांकित नवीन वस्तुओं सम्मिलित किया जाता है :—

**अनुक्रमांक - 76 —** महिला एवं बाल विकास विभाग हेतु सामग्री :—

1— मेकेनिकल बेबी वेईग स्केल (प्लेटफार्म टाईप)

**अनुक्रमांक - 77 — लेबोरेटरी/वेइंग स्केल/ग्रीन नेट/ग्रीन हाउस/पॉली हाउस सामग्री :—**

क्र.	सामग्री का नाम
1.	Lab Chemical
2.	Plate From type Electric Weighing Machine
3.	Mulching Sheet
4.	Pond Lining
5.	Dunnage Pallets

छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 के (यथा संशोधित 2022) के नियम-3 के अधीन परिशिष्ट-2 सूची में निम्नांकित नवीन वस्तुओं सम्मिलित किया जाता है :—

**अनुक्रमांक-32 — कृषि विभाग हेतु सामग्री :—**

क्र.	सामग्री का नाम
1.	Lab Chemical (केवल कृषि विभाग के उपयोग हेतु)
2.	Green House With Fan & Pad Cooling System (केवल कृषि विभाग के उपयोग हेतु) Shade Net House (केवल कृषि विभाग के उपयोग हेतु) Pastic Tunnel, (केवल कृषि विभाग के उपयोग हेतु) Root Trainer, (केवल कृषि विभाग के उपयोग हेतु) Poly House, (केवल कृषि विभाग के उपयोग हेतु)
3.	Shade Net/Green Net (केवल कृषि विभाग के उपयोग हेतु)
4.	Pump Set, Accessories (केवल कृषि विभाग के उपयोग हेतु)
5.	Hdpe Portable Vermi Compost Bed (केवल कृषि विभाग के उपयोग हेतु)
6.	Drip System (For Horticulture Crop) (केवल कृषि विभाग के उपयोग हेतु)
7.	Sprinkler System (for Agriculture Crop) (केवल कृषि विभाग के उपयोग हेतु)
8.	Plate From Type Electronic Weighing Machine (केवल कृषि विभाग के उपयोग हेतु)
9.	Mulching Sheet (केवल कृषि विभाग के उपयोग हेतु)
10.	Pond Lining (केवल कृषि विभाग के उपयोग हेतु)
11.	Dunnage Pallets (केवल कृषि विभाग के उपयोग हेतु)
12.	Palntkton Grower (केवल कृषि विभाग के उपयोग हेतु)
13.	Seed Greding Procesing Unit (केवल कृषि विभाग के उपयोग हेतु)
14.	Machinery & Equipement For Parkritik Paimt Unit (केवल कृषि विभाग के उपयोग हेतु)
15.	Sugarcane Plant (Poly Bag Sugarcane) (केवल कृषि विभाग के उपयोग हेतु)
16.	Waste Decomposer (केवल कृषि विभाग के उपयोग हेतु)
17.	Horticulture Tools & Tool Kit (केवल कृषि विभाग के उपयोग हेतु)

उपरोक्त संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से प्रवृत्त हुई समझी जावेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
भुवनेश यादव, सचिव.

**नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग**  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 11 अप्रैल 2023

क्रमांक एफ 1-3/2023/18.—छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम पंचायतों को सम्मिलित करते हुए नगर पंचायत दाढ़ी, जिला-बेमेतरा गठित करने का अभिप्राय प्रकट करता है :—

**अनुसूची-1**

नगर पंचायत दाढ़ी में सम्मिलित ग्राम पंचायतों का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	जनसंख्या वर्ष 2011
1	दाढ़ी	3567
2	गिधवा	732
3	दमईडीह	681

**अनुसूची-2**

नगर पंचायत दाढ़ी की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित हैं :—

ग्राम पंचायत दाढ़ी, गिधवा तथा दमईडीह की सम्पूर्ण सीमाएं ही नगर पंचायत दाढ़ी की सीमाएं होंगी.

उपरोक्त आशय के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 21 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति/सुझाव कलेक्टर-बेमेतरा को उनके कार्यालय में राज्य शासन के विनिश्चय हेतु कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**आर. एक्का**, संयुक्त सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 11 अप्रैल 2023

क्रमांक एफ 1-3/2023/18.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-3/2023/18 दिनांक 11-04-2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**आर. एक्का**, संयुक्त सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar the 11th April 2023

No. F 1-3/2023/18.—In exercise of powers conferred by section 5 of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby, intend to include the following Gram Panchayat in the boundary of

Nagar Panchayat Dadhi in District-Bemetara as given in the Schedule below :—

Schedule-1

The particulars of areas of Gram panchayat to be included in limits of Nagar Panchayat Dadhi is as under :—

S. No.	Name of Gram panchayat	population year 2011
1	Dadhi	3567
2	Gidhwa	732
3	Damaidih	681

Schedule-2

The boundaries of the proposed Nagar Panchayat Dadhi is as under :—

The Boundaries of the Nagar Panchayat Dadhi shall be the Total boundaries of existing Gram Panchayat Dadhi, Gidhwa and Damaidih.

Any person or any local authority may submit his objection/Suggestion in writing to the Collector, District-Bemetara on any official day and time within 21 days from the date of Publication in “Chhattisgarh Rajpatra” for the consideration of State Government.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
R. EKKA, Joint Secretary.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 11 अप्रैल 2023

क्रमांक एफ 1-4/2023/18.—छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम पंचायत को नगर पंचायत सरसीवां, जिला-सारंगढ़ बिलाईगढ़ गठित करने का अभिप्राय प्रकट करता है :—

अनुसूची-1

नगर पंचायत सरसीवां की सीमा में सम्मिलित किये जाने वाले ग्राम पंचायत क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	जनसंख्या वर्ष 2011
1	ग्राम पंचायत सरसीवां	6216

अनुसूची-2

नगर पंचायत सरसीवां की प्रस्तावित सीमाएं निम्नानुसार है :—

ग्राम पंचायत सरसीवां की सीमाएं ही नगर पंचायत सरसीवां की सीमाएं होंगी.

अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 21 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्ति/सुझाव कलेक्टर-सारंगढ़ बिलाईगढ़ को उनके कार्यालय में राज्य शासन के विनिश्चय हेतु कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. एक्का, संयुक्त सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 11 अप्रैल 2023

क्रमांक एफ 1-4/2023/18.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-4/2023/18 दिनांक 11-04-2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. एक्का, संयुक्त सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar the 11th April 2023

No. F 1-4/2023/18.—In exercise of powers conferred by section 5 of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby, intend to Constitute Gram Panchayat Sarsiwan as Nagar Panchayat Sarsiwan in District-Sarangarh Bilaigarh as per the Schedule given below :—

#### Schedule-1

The particulars of areas of Gram panchayat to be included in the limits of Nagar Panchayat Sarsiwan is as under :—

S. No.	Name of Gram panchayat	population year 2011
1	Gram panchayat Sarsiwan	6216

#### Schedule-2

The boundaries of the proposed Nagar Panchayat Sarsiwan is as under :—

The Boundaries of the Nagar Panchayat Sarsiwan shall be the boundaries of Gram Panchayat Sarsiwan.

Any person or any local authority may submit his objection/Suggestion in writing to the Collector, District-Sarangarh Bilaigarh on any official day and time within 21 days from the date of Publication in “Chhattisgarh Rajpatra” for the consideration of State Government.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
R. EKKKA, Joint Secretary.



**राजस्व विभाग**

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सक्ती, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं  
आपदा प्रबंधन विभाग

सक्ती, दिनांक 9 मार्च 2023

क्रमांक 702/अ-82/2022-23.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

**अनुसूची**

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सक्ती	डभरा	बालपुर प.ह.नं. 41	3.408	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा (अ.मु.) खरसिया, जिला रायगढ़ (छ.ग.).	बालपुर माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

सक्ती, दिनांक 9 मार्च 2023

क्रमांक 704/अ-82/2022-23.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

**अनुसूची**

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सक्ती	डभरा	कलमा प.ह.नं. 26/41	2.017	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा (अ.मु.) खरसिया, जिला रायगढ़ (छ.ग.).	कलमा माइनर-1 एवं बेलपाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

सक्ती, दिनांक 9 मार्च 2023

क्रमांक 706/अ-82/2022-23.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सक्ती	डभरा	बिलाईगढ़ प.ह.नं. 40	0.448	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा (अ.मु.) खरसिया, जिला रायगढ़ (छ.ग.).	कलमा माइनर-2 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

सक्ती, दिनांक 9 मार्च 2023

क्रमांक 708/अ-82/2022-23.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सक्ती	डभरा	कलमा प.ह.नं. 26/41	3.176	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा (अ.मु.) खरसिया, जिला रायगढ़ (छ.ग.).	कलमा माइनर-2 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
नूपुर राशि पन्ना, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं  
आपदा प्रबंधन विभाग**

रायगढ़, दिनांक 13 फरवरी 2023

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202301042100040/अ-82/2022-23.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

**अनुसूची**

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	गोतमा प.ह.नं. 34	0.020	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अ.मु. खरसिया, रायगढ़, जिला-रायगढ़ (छ.ग.).	केलो परियोजना के अंतर्गत टिनमिन माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 फरवरी 2023

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202207042100021/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

**अनुसूची**

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	बुनगा प.ह.नं. 21	0.073	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अ.मु. खरसिया, रायगढ़, जिला-रायगढ़ (छ.ग.).	केलो परियोजना के अंतर्गत बुनगा माईनर-1 नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 फरवरी 2023

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202302042100051/अ-82/2022-23.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	बालमगोड़ा प.ह.नं. 19	0.138	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अ.मु. खरसिया, रायगढ़, जिला-रायगढ़ (छ.ग.).	केलो परियोजना के अंतर्गत कुसमुरा माइनर व औराभाठा माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 फरवरी 2023

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202302042100052/अ-82/2022-23.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	नवापारा (मांड) प.ह.नं. 17	0.275	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अ.मु. खरसिया, रायगढ़, जिला-रायगढ़ (छ.ग.).	केलो परियोजना के अंतर्गत धनगांव माइनर-1 व धनगांव सब माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 फरवरी 2023

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202302042100053/अ-82/2022-23.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	पुटकापुरी प.ह.नं. 16	0.093	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अ.मु. खरसिया, रायगढ़, जिला-रायगढ़ (छ.ग.).	केलो परियोजना के अंतर्गत पुटकापुरी माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 फरवरी 2023

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202302042100054/अ-82/2022-23.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	टिनमिनी प.ह.नं. 34	1.449	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अ.मु. खरसिया, रायगढ़, जिला-रायगढ़ (छ.ग.).	केलो परियोजना के अंतर्गत छिछौर उमरिया टेल माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 मार्च 2023

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202302042100086/अ-82/2022-23.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	सिंहा प.ह.नं. 35	1.236	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अ.मु. खरसिया, रायगढ़, जिला-रायगढ़ (छ.ग.).	केलो परियोजना के अंतर्गत जिलाड़ी माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 मार्च 2023

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202302042100087/अ-82/2022-23.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	सिंहा प.ह.नं. 35	1.409	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अ.मु. खरसिया, रायगढ़, जिला-रायगढ़ (छ.ग.).	केलो परियोजना के अंतर्गत सिंहा माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
तारन प्रकाश सिन्हा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 13 अप्रैल 2023

क्रमांक/4602/भू-अर्जन/2023.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

**अनुसूची**

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर-रामानुजगंज	बलरामपुर	सुरी प.ह.नं. 25	0.340	कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, अम्बिकापुर (छ.ग.).	सुरी-अमडण्डा मार्ग पर चनान नदी पर निर्माणाधीन सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बलरामपुर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**विजय दयाराम के.,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर,  
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 22 मार्च 2023

क्रमांक/103(A)/वा./भू.अ./प्र.क्र./202103141400001/  
अ-82/20-21.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

**अनुसूची**

- (1) भूमि का वर्णन—  
(क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर  
(ख) तहसील-पखांजूर  
(ग) नगर/ग्राम-छोटेकापसी/वल्लभनगर  
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.092 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
919/2	0.044
919/4	0.004
418/1	0.012

(1)	(2)
421	0.032
योग	04
	0.092
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कापसी-पखांजूर मार्ग के कि.मी. 64/2 पर त्रास नाला पर सेतुमय पहुंचमार्ग निर्माण कार्य हेतु.	
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, पखांजूर के कार्यालय में किया जा सकता है.	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रियंका शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़  
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व  
एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 21 फरवरी 2023

प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2021-22.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—  
(क) जिला-रायगढ़  
(ख) तहसील-तमनार  
(ग) नगर/ग्राम-पंडिगांव  
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.108 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
503/4	0.048
504/2	0.060
योग	02
	0.108

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण (भ./स.) रायगढ़ संभाग रायगढ़ को परियोजना अंतर्गत पालीघाट-अमलीढोढ़ा मार्ग निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घरघोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 21 फरवरी 2023

प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2021-22.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—  
(क) जिला-रायगढ़  
(ख) तहसील-तमनार  
(ग) नगर/ग्राम-अमलीढोढ़ा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.115 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
199/2	0.057
199/3	0.058
योग	02
	0.115

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण (भ./स.) रायगढ़ संभाग रायगढ़ को परियोजना अंतर्गत पालीघाट-अमलीढोढ़ा मार्ग निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घरघोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.



रायगढ़, दिनांक 21 फरवरी 2023

अनुसूची

प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2021-22.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

## (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-रायगढ़  
(ख) तहसील-तमनार  
(ग) नगर/ग्राम-जोबरो  
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.016 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
288	0.006
289/1	0.005
289/2	0.005
योग	03
	0.016

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण (भ./स.) रायगढ़ संभाग रायगढ़ को परियोजना अंतर्गत पालीघाट-अमलीढोड़ा मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घरघोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 मार्च 2023

भू-अर्जन प्र. क्रमांक 343/202112042900043/अ-82/20021-22.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-रायगढ़  
(ख) तहसील-खरसिया  
(ग) नगर/ग्राम-बड़ेदेवगांव  
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.2019 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
436	0.007
433	0.021
439/1क, 440/1क	0.0003
432	0.018
429/1	0.010
573/3/ड	0.003
426/3, 426/5	0.006
438/2	0.003
438/4	0.006
448/1	0.007
450/1	0.021
449/2	0.003
449/1	0.003
469/2	0.006
469/1	0.005
112/3	0.026
330/2	0.0043
470/1	0.009
14	0.010
113/2	0.018
475	0.024
348/2	0.003
.2/11	0.006
575/2	0.009
283/1	0.0054
.11/2	0.006
476/3	0.006
342/1	0.004
120	0.036
341/5	0.004
341/4	0.003
341/2	0.006
341/1	0.012
486/22	0.003
486/14	0.003
486/18	0.004
486/2	0.003

(1)	(2)	(1)	(2)
486/5/च	0.004	.10/3	0.004
486/4/क	0.006	.9/1	0.016
486/5/घ	0.004	126/1/क, 131/2	0.020
490/1	0.006	84/1	0.0066
490/3	0.004	84/7	0.0034
490/7	0.003	84/4	0.006
490/6	0.010	112/2	0.012
48	0.028	121/1, 121/4	0.020
491/4/2, 491/5/2	0.003	121/2	0.005
491/4/1, 491/5/1	0.003	121/3	0.002
491/1	0.009	121/5	0.0091
573/2क/2	0.003	136/9	0.005
573/3क/2	0.0018	136/16	0.0024
573/2/क/5	0.0015	136/14	0.002
573/3/क/5	0.0016	136/15	0.001
573/2/क/3	0.0012	136/13	0.001
573/3/क/3	0.0016	136/17	0.003
.2/10	0.001	122	0.011
282/4	0.0014	123	0.013
337, 338	0.005	132/1	0.030
336/4	0.0022	138/1	0.007
336/3	0.0014	136/5	0.003
336/2	0.0014	.2/16	0.001
336/1	0.0012	.2/8	0.001
335/1/घ	0.004	486/9	0.007
.13/2	0.019	486/10	0.008
334/2	0.003	486/16	0.003
289	0.004	486/17	0.002
11/1, 12/1	0.0074	486/19/ख	0.003
113/1	0.008	486/19/क	0.001
332/3	0.0045	486/20	0.005
332/2	0.0033	486/21	0.005
332/6	0.0016	426/1	0.006
332/5	0.0017	348/1	0.007
331/1	0.004	347/1	0.009
331/3	0.004	345/3	0.007
331/4	0.005	486/1/8	0.010
330/1	0.0054	49/6/2	0.013
329/2	0.0066	345/4/क, 345/4/ख	0.0136
126/1/घ	0.003	345/1	0.008
126/1/ज	0.006	344/1	0.001
127, 128, 129/1, 129/2, 130	0.02	344/2	0.007
346/4	0.02	343/2	0.004
329/1	0.005	343/3	0.004
133/2	0.002	342/5	0.001
12/2ख	0.010	342/7	0.001
12/2क	0.010	283/7	0.0045

(1)	(2)	(1)	(2)
573/2/क/4	0.0017	47/4	0.0025
573/3/क/4	0.0016	47/2	0.0015
573/2ग	0.008	47/3	0.0074
573/3/ग	0.002	47/1	0.014
573/3/घ	0.002	.15/2	0.007
575/1	0.001	.15/3	0.007
575/3	0.002	.2/1	0.0005
573/3/क/1	0.0018	.2/5	0.0005
574/2/ग/1	0.003	.2/6	0.004
574/2/ग/2	0.003	.2/7	0.0016
574/4	0.0013	428	0.008
283/6	0.0017	342/2	0.001
133/3	0.003	486/4/ङ	0.002
282/1	0.0130	486/4/ख	0.002
131/1	0.0056	47/6	0.0015
.2/3	0.001	47/5	0.008
282/2	0.0014	573/2क/1	0.0013
282/3	0.0014	.2/12	0.0016
574/2/ख, 574/3/ख	0.0017	486/25	0.004
574/3/क	0.0016	573/3/ख	0.008
574/2/क	0.0018	2/2/घ	0.0048
137/1/क	0.002	84/8	0.008
137/1 ख, 138/4क	0.001	490/2	0.004
329/3	0.0016	426/2	0.012
328	0.006	332/4	0.0016
288	0.0033	136/8	0.004
287	0.0038	490/5	0.004
286/2	0.0015	342/2	0.002
286/1	0.0017		
285/2	0.011	योग	198
285/1	0.018		1.2019
75	0.0054	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सक्ती-टुन्ड्री	
49/12	0.0057	मार्ग कुल लंबाई 13.481 कि.मी. के उन्नयन एवं पुर्ननिर्माण	
49/15	0.0044	निर्माण कार्य हेतु.	
49/11	0.015	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी	
49/10	0.012	(रा.), खरसिया, जिला रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता	
49/1	0.010	है.	
49/6/3	0.0042	छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
49/6/1	0.0075	तारन प्रकाश सिन्हा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.	

## विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं  
आपदा प्रबंधन विभाग

सूरजपुर, दिनांक 1 मार्च 2023

प्रारूप-V  
(नियम 10 देखें)

क्रमांक 1/अ-82/2016-17.—जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजनार्थ पासल ग्राम, भैयाथान तहसील, सूरजपुर जिला में कुल 1.010 हे. भूमि अपेक्षित है, अर्थात्,

इसलिए घोषणा की जाती है कि उपयुक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो 1.010 हे. है जो ग्राम पासल, तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर में है. धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि का औद्योगिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है. जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :—

क्र.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (हेक्टेयर में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	उ.	द.	पू.	प.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	249	शासकीय पट्टा धारक	डांड	0.205	रघु आ. रतन, पीताम्बर आ. रतन, शान्ति पुत्री रतन संतोषी पुत्री रतन ग्राम पासल, भैयाथान	खसरा क्र. 250	खसरा क्र. 248	खसरा क्र. 253/1	कच्ची सड़क
2	252	भूमि स्वामी	डांड	0.015	बउधा आ. समेलाल, भुनेश्वरी पुत्री समेलाल निवासी पंडोपारा चन्द्रपुर सूरजपुर	खसरा क्र. 253/2	खसरा क्र. 253/1	खसरा क्र. 253/3	खसरा क्र. 253/1
3	253/1	भूमि स्वामी	डांड	0.340	रघुनाथ आ. हिरासाय पंडोपारा निवासी ग्राम पासल, भैयाथान	खसरा क्र. 253/2	खसरा क्र. 253/3	खसरा क्र. 252, 253/3	खसरा क्र. 248, 249
4.	255/2	भूमि स्वामी	डांड	0.450	नन्दलाल आ. बुधराम निवासी ग्राम पासल भैयाथान	खसरा क्र. 255/1, 253/1	खसरा क्र. 256/2	खसरा क्र. 260 रेड़ नदी	खसरा क्र. 255/3

वृक्ष	
किस्म	संख्या
महुआ	02
आम	01
साल	01
पीपल	01
परसा	01

संरचनाएं	
प्रकार	प्लिंथ एरिया
निरंक	निरंक

यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है।

ग्राम पासल तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर अन्तर्गत 1.010 हे. भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने नहीं हैं। खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, अर्जन लघु जल विद्युत परियोजना निर्माण हेतु किया जा रहा है,

जिला भूमि अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भैयाथान के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है। पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार संलग्न है।

इप्पफत आरा,  
कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.

## उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 1st February 2023

No. 13/L.G./2023/II-3-2/2009.—Shri Jaideep Vijay Nimonkar, District & Sessions Judge, Bemetara is hereby, granted earned leave for 03 days from 15-11-2022 to 17-11-2022 along with permission to remain out of headquarters during the said period and earned leave for 06 days from 21-11-2022 to 26-11-2022 along with permission to remain out of headquarters from afternoon of 21-11-2022 till the evening of 22-11-2022.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Nimonkar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 203 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 1st February 2023

No. 14/L.G./2023/II-3-28/2009.—Shri Santosh Kumar Aditya, II Additional principal Judge, Family Court, Raipur is hereby, granted earned leave for 03 days form 27-10-2022 to 29-10-2022 and earned leave for 10 days from 15-12-2022 to 24-12-2022 along with permission to remain out of headquarters from 15-12-2022 to 25 -12-2022.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Aditya, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 262 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 1st February 2023

No. 15/L.G./2023/II-3-39/2007.—Shri Gaukaran Singh Kunjam, the then Judge, Family Court, Jushpur is hereby, granted earned leave for 06 days from 18-04-2022 to 23-04-2022 along with permission to remain out of headquarters after the office hours of 13-04-2022 to till before the office hours of 25-04-2022 and earned leave for 15 days from 26-08-2022 to 09-09-2022 along with permission to remain out of headquarters, earned leave for 04 days from 04-11-2022 to 07-11-2022 along with permission to remain out of headquarters from 04-11-2022 to 08-11-2022, earned leave for 08 days from 21-11-2022 to 28-11-2022 along with permission to remain out of headquarters from 19-11-2022 to 28-11-2022 and earned leave for 02 days from 01-12-2022 to 02-12-2022 along with permission to remain out of headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Kunjam, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 267 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 1st February 2023

No. 16/L.G./2023/II-2-10/2007.—Shri K. Vinod Kujur, Registrar (Judicial), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 09 days from 10-11-2022 to 18-11-2022.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Kujur, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 1st February 2023

No. 17/L.G./2023/II-3-28/2008.—Smt. Girija Devi Meravi, Judge, Family Court, Balod is hereby, granted earned leave for 03 days from 29-12-2022 to 31-12-2022 with winter vacation along with permission to remain out of headquarters from 25-12-2022 till before the Court hours of 02-01-2023.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Meravi, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 297 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 1st February 2023

No. 18/L.G./2023/II-2-4/2009.—Shri Ashok Kumar Sahu, District & Sessions Judge, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 03 days from 29-12-2022 to 31-12-2022 with winter vacation along with permission to remain out of headquarters from 25-12-2022 to 31-12-2022.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Sahu, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 1st February 2023

No. 19/L.G./2023/II-2-28/2022.—Smt. Geeta Neware, Judge, Family Court, Jashpur is hereby, granted earned leave for 07 days from 25-12-2022 to 31-12-2022 along with permission to remain out of headquarters from 25-12-2022 till before the Court hours of 02-01-2023.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Neware, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 1st February 2023

No. 20/L.G./2023/II-3-14/2003.—Shri Rakesh Bihari Ghore, District & Sessions Judge, Surguja (Ambikapur) is hereby, granted earned leave for 04 days from 31-12-2022 to 03-01-2023 with winter vacation along with permission to remain out of headquarters after the Court hours of 24-12-2022 till 03-01-2023.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Ghore, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+09 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 1st February 2023

No. 21/L.G./2023/II-3-27/2014.—Shri Jitendra Kumar, Special Judge, ST & SC (PA) Act, Raigarh is hereby, granted earned leave for 04 days from 10-12-2022 to 13-12-2022 along with permission to remain out of headquarters after the Court hours of 09-12-2022 till before the Court hours of 14-12-2022.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Jitendra Kumar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 1st February 2023

No. 22/L.G./2023/II-2-8/2021.—Shri Rajeev Kumar, Special Judge (Atrocities), Korba is hereby, granted earned leave for 06 days from 05-12-2022 to 10-12-2022 along with permission to remain out of headquarters after the Court hours of 03-12-2022 till before the Court hours of 12-12-2022, earned leave for 03 days from 01-01-2023 to 03-01-2023 in continuation of winter vacation along with permission to remain out of headquarters after the Court hours of 24-12-2022 till before the Court hours of 04-01-2023 and earned leave for 06 days from 23-01-2023 to 28-01-2023 along with permission to remain out of headquarters after the Court hours of 20-01-2023 till before the Court hours of 30-01-2023.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Rajeev Kumar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 48 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 1st February 2023

No. 23/L.G./2023/II-2-11/2017.—Dr. Pragya Pachouri, District & Sessions Judge, Balod is hereby, granted earned leave for 01 day on 10-12-2022 along with permission to remain out of headquarters, earned leave for 05 days from 02-01-2023 to 06-01-2023 along with permission to remain out of headquarters and child-care-leave for 05 days from 16-01-2023 to 20-01-2023 along with permission to remain out of headquarters from 14-01-2023 to 22-01-2023.

During the period of earned leave & child-care-leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Dr. Pachouri, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 161 days of earned leave & 725 days of child-care-leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 1st February 2023

No. 24/L.G./2023/II-3-40/2010.—Shri Vijay Kumar Hota, Judge Family Court, Bemetara is hereby, granted earned leave for 03 days from 18-10-2022 to 20-10-2022 along with permission to remain out of headquarters after the office hours of 17-10-2022 till 20-10-2022, earned leave for 05 days from 27-10-2022 to 31-10-2022 along with permission to remain out of headquarters from 25-10-2022 till before the office hours of 01-11-2022, earned leave for 01 day on 28-11-2022 along with permission to remain out of headquarters after the office hours of 26-11-2022 till before the office hours of 29-11-2022, earned leave for 04 days from 05-12-2022 to 08-12-2022 along with permission to remain out of headquarters from 04-12-2022 till before the office hours of 09-12-2022 and earned leave for 01 day on 23-12-2022 along with permission to remain out of headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Hota, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 299 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,  
AWADH KISHORE, Additional Registrar (ADMN.)